



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2006/भाद्र 14, 1928

No. 133]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2006/BHADRA 14, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 31 अगस्त, 2006

सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की भाषा 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, हल्दिया स्थित कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु, कोलकाता पत्तन न्यास के प्रस्ताव से संबद्ध प्रकरण को संलग्न आदेशानुसार खत्म करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/56/2005- केओपीटी

कोलकत्ता पत्तन न्यास (केओपीटी)

आवेदक

आदेश

(अगस्त 2006 के 23वें दिन पारित)

यह प्रकरण हल्दिया स्थित कोलकत्ता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया-अनुसूची के संशोधन हेतु, कोलकत्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित है।

2. कोलकत्ता पत्तन न्यास से सितंबर 2005 में प्राप्त प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और निर्धारित सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उसपर कार्रवाई की गयी थी। केओपीटी ने दिनांक 20 मार्च 2006 को प्राधिकरण के कार्यालय में संदर्भित प्रकरण पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। दिनांक 29 मार्च 2006 को संदर्भित प्रस्ताव पर एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गयी थी। संयुक्त सुनवाई के अवसर पर अध्यक्ष (केओपीटी) ने यह अनुरोध किया कि प्रस्तुतीकरण के दौरान की गयी टिप्पणियों की दृष्टि से प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए कुछ अधिक समय प्रदान किया जाय।

3. अब केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई 2006 द्वारा अन्य बातों के साथ, निम्नांकित भी सूचित किया है:-

- (i). केओपीटी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भूखण्ड नीति दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप तथा महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों की दृष्टि से, हल्दिया और कोलकाता में स्थित केओपीटी भूमि और भवनों का नया मूल्यांकन आरंभ करेगा और एक नया संशोधित प्रस्ताव दाखिल करेगा।
- (ii). उसके दिनांक 16 सितंबर 2005 के संदर्भित प्रस्ताव को समाप्त माना जाय।
- (iii). हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को संशोधन तक विस्तारित किया जाय।

4.1. चूंकि केओपीटी ने, भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये भूखण्ड नीति दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों की दृष्टि से, हल्दिया और कोलकाता में स्थित अपनी भूमि और भवनों का नया मूल्यांकन करने का निर्णय ले लिया है, यह प्राधिकरण संदर्भित प्रकरण को खत्म करने तथा केओपीटी के दिनांक 16 सितंबर 2005 के प्रस्ताव को वापिस लिया मानने के लिए इच्छुक है। केओपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की अधिसूचना तिथि से 90 दिन के अंतर्गत दाखिल करें।

4.2. इस प्राधिकरण ने, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, 31 दिसंबर 2005 के आगे, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु, दिनांक 16 सितंबर 2005 के प्रस्ताव से संबंधित प्रकरण में पारित किये जानेवाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, विस्तार प्रदान करते हुए दिनांक 27 दिसंबर 2005 को एक आदेश पारित किया था। चूंकि यह प्रकरण खत्म किया गया है हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता को, विस्तार प्रदान करना आवश्यक है। चूंकि केओपीटी को हल्दिया स्थित अपनी भूमि और भवनों के साथ-साथ कोलकाता स्थित अपनी भूमि और भवनों का भी नए सिरे से मूल्यांकन करना है, यह प्राधिकरण केओपीटी के हल्दिया स्थित भूमि और भवनों के किराए की अनुसूची की वैधता, इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से, अधिकतम 6 माह के लिए विस्तारित करने को प्रवृत्त है।

4.3. भारत सरकार के पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने, केओपीटी समेत सभी महापत्तनों के लिए संशोधित भूखण्ड नीति दिशा-निर्देश घोषित किए हैं। संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी महापत्तनों में पट्टा किरायों को विनियमित करने के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी भूमि नीति निर्देशों का प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाने की अपेक्षा करते हैं। केओपीटी में भूमि के आबंटन हेतु वर्तमान दरमान में कुछ सशर्तताओं को भूमि नीति संबंधी घोषणा के प्रकाश में संशोधित करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी भूमि तथा भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किया जानेवाला प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा पारित (किये जानेवाले) आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, केओपीटी को भूखण्ड नीति मार्गदर्शनों में निर्धारित शर्तों का क्रियान्वयन करना चाहिए। तदनुसार, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के आबंटन की किराया अनुसूची में प्रचलित सशर्तताएँ तथा कोलकाता की भूमि के आबंटन से संबद्ध दरमान, उस सीमा तक संशोधित मान लिए जाएंगे जिस सीमा तक ऐसी सशर्तताएँ सरकार द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों से असंगत या भिन्न होंगे। केओपीटी को निर्देशित किया जाता है कि वह निम्नलिखित सामान्य टिप्पण को अपनी किराया अनुसूची तथा दरमान में समाविष्ट करें।

“अभिव्यक्त की गयी सभी शर्तें/टिप्पणियाँ उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक वे सरकार द्वारा घोषित फरवरी 2004 की भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों से असंगत नहीं है। अगर मतभेद हुआ तो सरकार द्वारा भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तें प्रचलित होंगी।”

5. परिणामस्वरूप, ऊपर दिये गये कारणों से तथा समस्त विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, इस प्रकरण को वपिस लिए गए के रूप में खत्म करने को निर्णय लेता है तथा हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, छः माह की अवधि के लिए अथवा कोलकत्ता और हल्दिया की केओपीटी भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक इनमे से जो भी पहले हो विस्तारित करता है। केओपीटी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से 90 दिन के भीतर अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करें।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st August, 2006

No. TAMP/56/2005-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating to the proposal of the Kolkata Port Trust (KOPT) for revision of Schedule of rent for land and buildings of KOPT at Haldia as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/56/2005 – KOPT

Kolkata Port Trust (KOPT)

Applicant

ORDER

(Passed on this 23rd day of August 2006)

This case relates to a proposal from the Kolkata Port Trust (KOPT) for revision of the Schedule of Rent for land and buildings of KOPT at Haldia.

2. The proposal received from the KOPT in September 2005 was registered as a tariff case and processed following the usual consultation process prescribed. The KOPT made a presentation on the case in reference in the office of the Authority on 20 March 2006. A joint hearing was held on 29 March 2006 on the proposal in reference. At the joint hearing Chairman (KOPT) requested to allow some more time to enable KOPT to review the proposal in the light of the observations made during the presentation.

3. Now, the KOPT vide its letter dated 25 July 2006 has conveyed to this Authority, *inter alia* the following:

- (i). It will undertake a fresh valuation of land and buildings of KOPT at Haldia and Kolkata in line with the provisions of the Land Policy Guidelines approved by Central Government and in the light of observations made by the TAMP and file a fresh revised proposal.
- (ii).. To treat its proposal dated 16 September 2005 in reference as closed.
- (iii). The validity of the existing Rent Schedule of Land and Buildings of KOPT at Halida may be extended till revision.

4.1. Since the KOPT has decided to undertake fresh valuation of its Land and Buildings at Haldia and at Kolkata in line with the revised Land Policy guidelines announced by the Government of India and in the light of observations

made by this Authority, this Authority is inclined to close the case in reference and treat the KOPT's proposal dated 16 September 2005 as withdrawn. The KOPT is advised to file its revised proposal within 90 days from the date of Notification of the Order passed by the Authority.

4.2. This Authority had passed an Order dated 27 December 2005, extending the validity of the existing Rent Schedule for Land and Buildings of KOPT at Haldia beyond 31 December 2005 till the effective date of implementation of the Order to be passed in the case relating to the KOPT's proposal dated 16 September 2005 for revision of Rent Schedule for Land and Buildings of KOPT situated at Haldia. Since the case is closed, the validity of the existing Rent Schedule of Land and Buildings of KOPT at Haldia needs to be extended. Since the KOPT has to undertake a fresh valuation of Land and Buildings of KOPT at Kolkata in addition to its Land and Buildings at Haldia, this Authority is inclined to extend the validity of the Rent Schedule for Land and Buildings of KOPT at Haldia for a maximum period of six months from date of Notification of this Order.

4.3. The Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (MSRTH) has announced revised Land Policy guidelines for major ports including the KOPT. The revised tariff guidelines require this Authority to follow the Land Policy guidelines issued by the Government of India in the matter of regulating lease rentals at the major ports. Some of the conditionalities in the existing Scale of Rates for allotment of land at KOPT may require modifications in the light of the land policy announcement. Till such time the effective date implementation of Order (to be) passed by this Authority on the proposal to be filed by KOPT for revision of its Schedule of Rent for Land and Buildings, the KOPT should implement the conditions prescribed in the policy guidelines. Accordingly, the existing conditionalities in the Rent Schedule for allotment of Land and Buildings of KOPT at Haldia and the relevant Scale of Rates for allotment of land at Kolkata will stand amended to the extent such conditionalities are inconsistent or at variance with the Land Policy guidelines issued by the Government. The KOPT is directed to incorporate the following General Note in its Rent Schedule and Scale of Rates:

"All the conditions / notes stated shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Land Policy guidelines of February 2004 announced by the Government. In case of disagreement, the conditions prescribed by the Government in the Land Policy guidelines shall prevail."

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to close this case as withdrawn and extends the validity of the existing Rent Schedule of Land and Buildings of KOPT at Haldia for a period of six months or till the effective date of Notification of Order passed by this Authority on the proposal filed by the KOPT for revision of Schedule of Rent for Land and Buildings of KOPT at Haldia and at Kolkata, whichever is earlier. The KOPT is directed to file its revised proposal within 90 days from the date of Notification of this Order.

A.L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT III/IV/143/2006/Exty.]